



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]
No. 12]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2017/ पौष 22, 1938
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2017/PAUSA 22, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2017

(निर्णयक समीक्षा)

(केस सं. एसएसआर 05/2017)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा जाँच की शुरुआत

फा. सं. 15/18/2016-डीजीएडी(केस सं. एसएसआर 05/2017).—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जाँच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2005 की अधिसूचना सं. 14/7/2005-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी और प्रारंभिक जाँच परिणाम दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. 14/7/2005-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 28 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. 14/7/2005-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 7 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं 94/2012- सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा पहली निर्णयिक समीक्षा दिनांक 1 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना सं. 15/15/2010-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी और अंतिम जाँच परिणाम प्राधिकारी द्वारा 30 नवंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 15/15/2010-डीजीएडी प्रकाशित किए गए थे और केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2012

की अधिसूचना सं 5/2012- सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को नवीकृत किया गया था। इस मामले में लगाया गया पाटन रोधी शुल्क दिनांक 12 जनवरी, 2017 को समाप्त होगा।

3. दूसरी निर्णयिक समीक्षा जाँच के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका की जाँच के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष था कि चीन जन. गण. से सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फ़िल्म के आयातों से संबंधित निर्णयिक समीक्षा की शुरुआत करने की कोई जरूरत नहीं है और तदनुसार निर्णयिक समीक्षा को अस्वीकार करते हुए दिनांक 26 दिसंबर, 2016 का का.आ. जारी किया गया। इस का.आ. के विरुद्ध घरेलू उद्योग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 146/2017 दायर की।

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अनुदेशों का सार नीचे उद्धृत किया जा रहा है :

“परिणामस्वरूप, प्रतिवादी को अनुदेश जारी किए जाते हैं - इस दौरान - याचिकाकर्ताओं के मामले में निर्णयिक समीक्षा आरंभ की जाए। इसी दौरान निर्णयिक समीक्षा और अधिसूचना तथा आदेशों में यह व्यवस्था की जाएगी कि यह कार्यवाही अपने आप ही रिट कार्यवाही के अन्तिम परिणाम के अध्यधीन होगी।

यह भी निर्देश दिया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रश्न कानून के अनुसार होगा।”

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार, एक निर्णयिक समीक्षा का मामला एतद्वारा निम्नलिखित विवरण के साथ शुरू किया जाता है:

विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की ओर से वर्तमान याचिका मै. केसोराम रेयान (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा दायर की गई है।

ख. निर्णयिक समीक्षा की शुरुआत

4. माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर उल्लिखित आदेशों के अनुपालन में, निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार निर्णयिक समीक्षा की शुरुआत करते हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फ़िल्म है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अधीन सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 39207111 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और इस जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

6. चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णयिक समीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पादन का दायरा वही रहेगा जैसे पूर्ववर्ती सम्पन्न निर्णयिक समीक्षा जाँच में था।

घ. प्रक्रिया

7. इस जाँच से यह निर्धारित होगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी इस बात की जाँच करेंगे कि क्या पाटन और परिणामी क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए शुल्कों को लागू रखना आवश्यक है।

- i. इस समीक्षा जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. है।
- ii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2012-मार्च 2013, अप्रैल 2013-मार्च 2014, अप्रैल 2014 - मार्च 2015 और जाँच अवधि शामिल होगी।
- iii. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकते हैं और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

क) कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।

ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।

ग) उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।

घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

ड. सूचना प्रस्तुत करना

8. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें:

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

9. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

च. समय-सीमा

10. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

11. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

छ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

12. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनके साथ साफ्ट प्रति भी होनी चाहिए।

13. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

15. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

16. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

17. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ज. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

18. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

झ. असहयोग

19. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डा. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2017

(Sunset Review)

(Case No. SSR 5/2017)

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of Cellophane Transparent Film, originating in or exported from China PR.

F. No. 15/18/2016-DGAD (Case No. SSR 5/2017).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority

(hereinafter also referred to as the Authority) recommended imposition of anti -dumping duty on imports of “Cellophane Transparent Film” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR.(hereinafter referred to as the subject country).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/7/2005- DGAD dated 27th September 2005 and preliminary finding was published by the Authority vide Notification No. 14/7/2005-DGAD dated 3rd February 2006. The final finding was published by the Authority vide Notification No.14/7/2005-DGAD dated 28th July 2006 and definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 94/2006 - CUS dated 7th September 2006. The First Sunset Review was initiated by the Authority vide Notification No. 15/15/2010- DGAD dated 1st December 2010 and the final findings were published by the Authority vide Notification No. 15/15/2010 dated 30th November 2011 and the definitive Anti-Dumping duty was renewed by the Central Government vide Notification No. 5/2012 – CUS dated 13th January 2012. The anti-dumping duties imposed in this case will expire on 12th January, 2017

3. Based on the examination of the petition filed by the Domestic Industry for the 2nd Sunset Review investigation, Authority came to the conclusion that there is no need to initiate the Sunset Review concerning imports of cellophane transparent film from China PR and accordingly, O.M. dated 26th Dec., 2016 was issued denying the request for Sunset Review. Against the O.M, the Domestic Industry filed the writ petition No. 146/2017 before the Hon'ble High Court of Delhi. The extracts of directions from Hon'ble High Court are reproduced as under:-

“Consequently, a direction is issued to the respondent to – in the course of the day – initiate the Sunset Review in the petitioners’ case. At the same time, the Sunset Review and notification as well as the orders shall carry a stipulation that the proceeding itself would be subject to the final outcome of the writ proceedings.

It is further directed that the question of imposition of Anti-Dumping duty would be in accordance with law.”

In compliance with the above stated directions of the Hon'ble High Court, a sunset review case is hereby initiated with the following details:

The present petition has been filed by M/s Kesoram Rayon (*hereinafter referred to as Petitioner*), on behalf of the domestic industry for the product under consideration.

B. Initiation of Sunset Review

4. Pursuant to the above stated orders of the Hon'ble High Court, the Designated Authority hereby initiates sunset review in accordance with section 9A(5) of the Custom Tariff(Amendment) Act read with Rule 23 of Antidumping Rules.

C. Product under Consideration and Like Article

5. The product under consideration in the present investigation is “Cellophane Transparent Film”. The product is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act under Customs Sub-heading No. 39207111. However, customs classification is indicative in nature and not binding on the scope of the investigation.

6. Since the proposed investigation is a sunset review investigation, the scope of the product under consideration is the same as that of the previously concluded sunset review investigation.

D. Procedure

7. The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether imposition of the duties is necessary to offset dumping and causing injury.

- i. The country involved in this review investigation is China PR.
- ii. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st July 2015 to 30th June 2016. The injury investigation period will however cover the periods April'2012-March'13, April'2013– March'2014, April'2014-March'2015 and the POI
- iii. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

While submitting questionnaire response, producer/ exporter may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production and sale of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

- (a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labor, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant state interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
- (b) Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
- (c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- (d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

E. Submission of Information

8. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

9. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

F. Time Limit

10. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

11. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

G. Submission of information on confidential basis

12. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a)marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page and accompanied with soft copies.

13. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

14. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

15. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible

to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

16. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

17. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

H. Inspection of public file

18. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

I. Non-cooperation

19. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority